अमर उजाला
प्रवाह
मोदी @ 3.0 पहला बजट 2024-25
महोत्सव विश्वास का
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948
नई दिल्ली ■ बुधवार, 24 जुलाई 2024

बजट सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। - जैक ल्यू

निरंतरता और फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार सातवां और मोदी 3.0 का जो पहला बजट पेश किया गया है, उसमें लोक-लुभावन घोषणाओं के बजाय वित्तीय अनुशासन और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाले दूरगामी कदमों पर जोर देते हुए निरंतर प्रवाह में कुछ नया जोड़ने की कोशिश दिखती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार सातवां और मोदी 3.0 का पहला बजट प्रस्तुत करते हुए उम्मीदों के अनुरूप लोक-लुभावन घोषणाओं के बजाय वित्तीय अनुशासन और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाले दूरगामी कदमों पर जोर दिया है। उन्होंने बजट भाषण में नरेंद्र मोदी सरकार की नौ प्राथमिकताएं बताईं, जो कृषि की उत्पादकता व लचीलापन, रोजगार व कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान व विकास और अगली पीढ़ी के सुधार हैं, और यही नए बजट का आधार भी हैं। बजट में शिक्षा व रोजगार पर विशेष ध्यान देते हुए नौकरियों और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी विशिष्ट योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनके तहत पांच साल में एक करोड़ युवाओं को इनरमंद बनाया जाएगा। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर चुकाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। कर ढांचे में बदलाव से संभावित रूप से करदाताओं को एक वर्ष में लगभग 17,500 रुपये का शुद्ध लाभ मिलेगा। राजस्व सृजन बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10 से 12.5 फीसदी कर दिया गया है। राजनीतिक सहयोगियों को खुश करने की खातिर बिहार के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपये, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, जो परियोजना आधारित निवेश है, जिससे रोजगार तो सृजित होगा ही, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। खेती-किसानी के लिए करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई, जो पिछली बार से 21.6 फीसदी ज्यादा है। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकासमान है, ऐसे में, नया बजट वास्तविक और भविष्योन्मुखी है, जिसमें पहले से चले आ रहे प्रवाह में कुछ नई चीजें जोड़कर इसे स्थायित्व देने का प्रयास किया गया है।

मजबूत नींव रखता बजट

यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप आगामी पांच साल के लिए ठोस नींव रखता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में राहत और प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें रोजगार सृजन, शहरी विकास और महिला कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

वर्ष 2024 का बजट अत्यधिक प्रत्याशित रहा, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद कि पिछला दशक आने वाले पांच वर्षों में अपेक्षित परिवर्तनकारी परिवर्तनों के लिए केवल एक प्रस्तावना या 'ट्रेलर' था। यह बजट नौ प्रमुख क्षेत्रों के आसपास संरचित है, जिसमें रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है, जो सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए 'अच्छी भुगतान वाली नौकरियां' निर्मित करने की अपनी प्राथमिकता में काफी स्पष्ट रही है। इस संबंध में, शिक्षा के लिए बढ़ा हुआ बजट आवंटन दूरगामी प्रभाव वाला एक रणनीतिक कदम है। दूसरी तरफ, कृषि अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य दूरगामी सोच वाले दृष्टिकोण को दर्शाते हुए उत्पादकता बढ़ाना है।

एक और उल्लेखनीय पहल रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन कार्यक्रम है, जहां सरकार भविष्य निधि में नियोक्ता का हिस्सा और ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नए कर्मचारियों के लिए पहले महीने का वेतन, जो पंद्रह हजार रुपये तक हो, कवर करेगी। इसके अतिरिक्त, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जो इस क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। कार्यबल में महिलाओं के लिए बढ़ा हुआ बजट आवंटन और शिक्षा ऋण की ब्याज दरों में तीन प्रतिशत की छूट समावेशी विकास की दिशा में सराहनीय कदम हैं। इसके अलावा, सरकार ने एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है जिसका लक्ष्य एक करोड़ भारतीय युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में आवासीय और व्यावसायिक अनुभव प्रदान करना है, ताकि शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को कम किया जा सके। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो राजनीति में विश्वस्त सहयोगी होने के नाते स्वाभाविक भी था। बिहार के लिए, कोसी नदी बेसिन में बाढ़ सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बजट क्रेडिट गारंटी योजना को बढ़ाना और मुद्रा लोन सीमा को रुपये 20 लाख तक बढ़ाने जैसे उपायों से एमएसएमई को आवश्यक वित्तीय सहायता मिलने, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मोहनदास पई

लेखक प्रख्यात विचारक, एरियन कैपिटल के चेयरमैन, पद्मश्री से सम्मानित और इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ और बोर्ड सदस्य हैं।

बजट में शहरी विकास को प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया है, जिसमें जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं परिवहन के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कई सुधारों के प्रस्ताव के साथ सरकार ने शहरी ढांचों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो सतत विकास एवं जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत का भविष्य शहरी क्षेत्रों पर ही निर्भर है। बजट में ऊर्जा परिवर्तन को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है, जिसमें सोलर रूफटॉप नीति की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की फंडिंग के लिए एक लाख करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र को शामिल किया गया है, जो नवाचार के महत्व को रेखांकित करता है। बजट में रोजगार, भूमि संबंधी मामलों और वित्तीय क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को रूपरेखा पेश की गई है, जिसका उद्देश्य व्यापार सुगमता को बढ़ाना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करना है। बजट प्राप्तियां बढ़कर 32.07 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं, जबकि राजकोषीय घाटा जो अंतरिम बजट में 5.1 फीसदी था, वह घटकर 4.9 फीसदी रह गया है। यह कमी मुख्य रूप से जीडीपी में वृद्धि, उच्च प्राप्तियों और कम व्यय के कारण आई है। 2023-24 के वास्तविक खातों से पता चलता है कि संशोधित बजट में निर्धारित 5.8 फीसदी की तुलना में राजकोषीय घाटा घटकर 5.6 फीसदी रह गया है। बजट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में कई तरह के बदलाव लाता है। हालांकि अप्रत्यक्ष करों, विशेष रूप से जीएसटी का सरलीकरण एक सकारात्मक कदम है। लेकिन कर कटौती एवं उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी जैसे कई मुद्दे अब भी हैं। कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी से शेयरबाजार में सूचीबद्ध निवेशकों के लिए चिंताएं बढ़ी हैं। सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है, जबकि शॉर्ट टर्म गेन पर टैक्स को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध, दोनों प्रतिभूतियों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को एक समान 12.50 फीसदी रखकर दोनों के बीच के अंतर को पाट दिया है। यह गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए दर में बड़ी कमी है, जिससे स्टार्ट-अप्स में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। सोना एवं चांदी पर कर घटाकर छह फीसदी कर दिए जाने से इनकी तस्करी तो घटेगी ही, मूल्यवर्धन एवं निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एंजल टैक्स हटाने से स्टार्ट-अप को भी बड़ी राहत मिली है। व्यक्तिगत करदाता के मामले में बजट ने कई लोगों को निराश किया है। जबकि प्रति व्यक्ति 17,500 रुपये की सकल कटौती के साथ कुछ कर राहत दी गई है। कर संरचना के छह स्लैब को बनाए रखना शायद अनावश्यक रूप से जटिल है। तीन-स्लैब की संरचना अधिक सरल होती।

बजट का एक और महत्वपूर्ण पहलू विवाद समाधान पर ध्यान केंद्रित करना है। विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत का उद्देश्य कुछ लंबित आयकर विवादों को हल करना है। प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन यह अधिक प्रभावी होता, यदि उच्च न्यायालय के निर्णयों का बेहतर सम्मान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए सीमा कम से कम 50 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी जाती। कुल मिलाकर, यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप आगामी पांच साल के लिए ठोस नींव रखता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में राहत और प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें रोजगार सृजन, शहरी विकास और महिला कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि, बजट मध्यम वर्ग की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है, जो लगातार कर बोझ उठाता है। पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि इक्विटी संस्कृति को भी कम कर सकती है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

उम्मीद पर दुनिया कायम है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 7,800 शब्दों वाले करीब नब्बे मिनट के बजट भाषण में वित्तीय इंजीनियरिंग की कुशलता व राजनीति का सटीक प्रबंधन दिखता है।

बजट दरअसल पवित्र राजनीतिक मंशा की एक अभिव्यक्ति होता है। सरकार के लिए यह राजनीतिक सहयोगियों को आश्वस्त करने का एक अवसर है, लेकिन साथ ही यह आर्थिक आवेगों को भी बढ़ावा देता है। 2024 का बजट राजनीतिक मजबूरियों और आर्थिक अनिवार्यताओं के चौराहे पर पहुंचा है। लोकसभा चुनावों के दौरान बयानबाजी का सिलसिला, सत्ताधारियों के संख्याबल में कमी और जीडीपी में वृद्धि व निजी उपभोग के दावों और 'फील-गुड' कारक के बीच की दूरी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उम्मीदें बढ़ा दी थीं। बजटों का शिल्प, कला और विज्ञान दोनों होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 7,800 शब्दों वाले करीब नब्बे मिनट के भाषण में आय पिरामिड में सबसे नीचे से आने वाली दर्द भरी चीखों का सुनना दिखता है। बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किए जाने की कोशिश है।

शंकर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार

बजट राजनीति का कुशल प्रबंधन वित्तीय इंजीनियरिंग में दिखाई देता है। बजट से पहले दो सहयोगियों तेदेपा और जदयू ने अपने समर्थन की कीमत जाहिर कर दी थी, जिसे पूरा भी किया गया है। नए बजट में वे सभी बातें हैं, जो लोग सरकार से सुनना चाहते हैं। बजट में नौ प्राथमिकताएं सूचीबद्ध हैं। बजट लोकलुभावन वादों को छोड़ संरचनात्मक दृष्टिकोण का विकल्प चुनता है। इसमें कृषि अनुसंधान, उच्च उपज वाले बीज जारी करने, प्राकृतिक खेती की शुरुआत, दालों और तिलहनों के लिए मिशन, खराब होने वाली वस्तुओं के लिए क्लस्टर, डिजिटल सर्वेक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार, मवेशियों और झींगा पालन के लिए वित्तपोषण की समीक्षा की पेशकश की गई। सरकार ने बेरोजगार युवाओं की बात सुनी और रोजगार से जुड़ा एक प्रोत्साहन कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें नियोक्ताओं को लागत में छूट, शिक्षार्थियों को वित्तीय मदद, और नौकरी चाहने वालों को मौके शामिल हैं। बजट टीम भारत के विचार को पुनर्जीवित करने के लिए एक रूपरेखा का वादा करती है, जिसमें राज्यों व केंद्र में समरूपता होगी। बजट में शहरीकरण की शक्ति को भी पहचाना गया है। इन्हें विकास का केंद्र माना गया है, लेकिन इतना काफी नहीं, क्योंकि भारत में शहरों के प्रबंधन को बदलने के लिए प्रतिमानों में बड़ा बदलाव जरूरी है। इसमें संदेह नहीं कि बजट में कई आशाजनक बिंदु हैं। सब कुछ कहने और हो जाने के बाद यह देखना बाकी है कि जो कहा गया है, वह पूरा होता है या नहीं। यह वास्तव में उम्मीद की लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है।

नौजवानों का वक्त

बजट में विकास और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। यह गतिशील और समावेशी आर्थिक वातावरण तैयार करेगा।

वित्त मंत्री ने अतीत में पेश किए बजटों में लगातार विकास और रोजगार सृजन के महत्व पर जोर दिया है। इस बार का बजट भी इन दोनों मोर्चों पर केंद्रित है। पहली बार नौकरी हासिल करने वाले को पहला वेतन सरकार सीधे उसके खाते में देगी। इससे करीब 2.10 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों को ही प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया गया है। ईपीएफओ का अंश देकर विनिर्माण क्षेत्र में औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका 30 लाख युवाओं को फायदा होगा। दो वर्ष तक सभी औपचारिक क्षेत्रों के नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों के ईपीएफओ में योगदान दिया जाएगा। इससे 50 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित होंगी।

अमिताभ कांत

कामकाजी महिलाओं के समर्थन पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, क्रेच एवं उद्योगों के सहयोग से महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के जरिये सरकार का उद्देश्य ज्यादा समावेशी कार्यबल तैयार करना है। एक हजार आईटीआई को अपग्रेड कर 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। एमएसएमई को वित्तीय, तकनीकी और विनियामक सहायता देने के लिए एक पैकेज पेश किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी की घोषणा की गई है। इससे एमएसएमई को बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के प्लांट और मशीनरी में निवेश करने की अनुमति मिलेगी। सरकार 100 करोड़ रुपये तक के ऋण की गारंटी देगी। बुनियादी ढांचे में निवेश का अर्थव्यवस्था की मजबूती पर काफी प्रभाव पड़ता है। 11.11 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता के साथ सरकार का ध्यान शहरी विकास और कनेक्टिविटी पर है। पूर्वी हिस्सों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए पूर्वोदय योजना शुरू की गई है। कुल मिलाकर, बजट रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का समग्र दृष्टिकोण पेश करता है। कृषि, विनिर्माण, सेवाओं, बुनियादी ढांचे और नवाचार में प्रगति का लाभ उठाकर, सरकार का लक्ष्य एक गतिशील और समावेशी आर्थिक वातावरण तैयार करना है। *(लेखक भारत में हुए जी-20 के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं।)*

आशा

बजट से कौशल विकास को मिलेगी धार

4,10,00,000

रोजगार होंगे सृजित

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सरकार तीन योजनाएं लागू करेगी, जिन पर पांच वर्षों में दो लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। पहली नौकरी का पहला वेतन देने के साथ ही सरकार ईपीएफओ में अंशदान करेगी।

अगले पांच वर्षों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। इसमें परिणाम और गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा। कंपनियों को ईपीएफ की मदद से 50 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे।

बाजार आखिरकार मजबूत ही होंगे

अजय बग्गा, आर्थिक विश्लेषक

इस बार का केंद्रीय बजट वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र, कृषि विकास, रोजगार सृजन, रोजगार के लिए तैयार युवाओं के कौशल विकास और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी संरचनाओं के निर्माण पर केंद्रित है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी बड़ी पहल राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.9 फीसदी तक लाने और इस वर्ष सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार को कम करने के दौरान की गई हैं।

इस बजट में वायदा और विकल्प अनुबंधों पर प्रतिभूति लेनदेन कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले अल्पकालिक लाभ पर अब 20 फीसदी कर लगेगा, जबकि पहले यह मात्र 15 फीसदी था। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर अब 12.5 फीसदी कर लगेगा, जबकि पहले यह 10 फीसदी था। कुछ वित्तीय साधनों पर कर योग्य पूंजीगत लाभ पर छूट की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना कर दी गई है।

निवेश और बाजार

बजट घोषणा के बाद बॉन्ड और रुपये में गिरावट आई। भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट आई, एनएसई निफ्टी 50 सूचकांक में 1.8 फीसदी की गिरावट आई, लेकिन नुकसान कम हुआ। स्मॉल कैप और मिडकैप सूचकांक में तेज गिरावट देखी गई, लेकिन निचले स्तरों पर खरीदारी के कारण दिन के अंत तक इनमें भी गिरावट देखी गई।

उच्च आयकर छूट के साथ-साथ सोना, चांदी, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी, साथ ही महिलाओं के लिए रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं और कार्यक्रमों से समग्र खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जबकि प्रत्यक्ष कर नीति में बदलाव से कई कमाने वालों के हाथ में कर चुकाने के बाद ज्यादा पैसे बच सकते हैं। रोजगार कार्यक्रमों पर खर्च से देश के युवाओं के हाथों में अधिक पैसा आ सकता है।

बजट घोषणाओं के बाद भारत की उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों और दोपहिया वाहन निर्माताओं को लाभ हुआ। प्रमुख राज्यों में स्थित बुनियादी ढांचा कंपनियों को भी निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से मदद मिली। सोने और चांदी पर शुल्क कटौती के कारण आभूषण कंपनियों के शेयरों में भी तेजी आई। बजट में कोई अतिरिक्त शुल्क की घोषणा नहीं किए जाने के बावजूद तंबाकू कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ गईं।

बजट में 'एंजल टैक्स' को खत्म करने से देश के स्टार्ट-अप सेक्टर को लाभ होगा। यह टैक्स स्टार्ट-अप द्वारा उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्यांकन पर जुटाए गए फंड पर लगाया जाता है। इससे देश में स्टार्ट-अप परिदृश्य को बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा से लेकर रेलवे, प्रॉपर्टी डेवलपर्स से लेकर निर्माण कंपनियों तक के प्रमुख शेयरों में मुनाफा वसूली देखी गई, जो कि भविष्य के उज्ज्वल अनुमानों के कारण काफी ऊपर चढ़े थे। बजट में रियल एस्टेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम किया गया है, लेकिन इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया गया है। यह एक ऐसा प्रावधान था, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के आधार पर कर देयता को कम करने की अनुमति देता था। परिणामस्वरूप रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई।

रेटिंग एजेंसियों ने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने और उधार कम करने की घोषणाओं की सराहना की है। पूंजी बाजार पूंजीगत लाभ करों में वृद्धि, बायबैक (अपने बकाया शेयरों की खरीद) को कराधान के दायरे में लाने और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में वृद्धि से बहुत खुश नहीं था। कुल मिलाकर, यह बजट संकटापन्न है और यह अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देगा, जिससे अंततः बाजारों को भी मदद मिलेगी।

edit@amarujala.com

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 24 जुलाई • 2024
www.rashtriyasahara.com

संतुलित बजट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का 2024 का बजट कई मामलों में संतुलित माना जाएगा। नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में राजग सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद यह पहला बजट है। बजट में निसंदेह मानव संसाधन विकास और बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्र सरकार वेतनभोगियों की उम्मीदों में वह खरी उतरीं। नई टैक्स व्यवस्था में अब स्टैंडर्ड डिडक्शन पचास हजार से बढ़ाकर पिच्हत्तर हजार रुपए कर दिया। वेतनभोगियों को इनकम टैक्स में 17,500 रुपए तक की बचत होगी। वित्तमंत्री का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट की छह महीने में समीक्षा की जाएगी। कैपिटल गेन छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्ति

पर स्टॉम्प ड्यूटी कम करने के साथ ही चुनिंदा शहरों में साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब डेवलप करने की योजना भी है। सौ बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज उपचार व ठोस अपशिष्ट परियोजनाओं की भी घोषणा की। देश में घरेलू कूच का परिचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था दी। सरकार ने स्पेस इकोनॉमी के लिए हजार करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसद व प्लैटिनयम पर 6.5 फीसद का प्रस्ताव रखा। टीडीएस में देरी को अपराध से बाहर कर सीतारमण ने नौकरीपेशा को राहत दी है। केंद्रीय बजट में युवाओं के रोजगार के लिए 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मुहैया कराने के साथ ही पांच हजार रुपए महीने स्टाइपेंड देने की भी बात की। बजट के जरिये सियासी समीकरण दुरुस्त करने और विपक्षी धार को कुंद करने की रणनीति के तहत सरकार ने अपने अहम सहयोगी दलों जेडी (यू) व टीडीपी शासित राज्यों बिहार व आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज दिया। हालांकि इस दिलदारी से बाकी राज्यों में सरकार के खिलाफ आवाज तेज होगी। खैर, जैसी उम्मीदें थीं, बजट वैसा नहीं रहा। विपक्ष का आरोप है कि बजट में गरीबों व आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। साथ ही इसे राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित भी बताया। राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ व कॉपी-पेस्ट बजट तक कह दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से स्थिर होने के बावजूद क्षेत्रीय असंतुलन गंभीर बना हुआ है। मगर तमाम चुनौतियों के बावजूद धन प्रबंधन करने में सीतारमण ने किसी को निराश नहीं होने देने की भरपूर कोशिश की है।

विचारपूर्ण हों निर्णय

कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड प्रशासन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। दो जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि खाना बेचने वालों को यह बताना जरूरी है कि वे किस तरह का खाना दे रहे हैं, लेकिन उस पर मालिक या कर्मचारियों का नाम सार्वजनिक करने के लिए जोर नहीं डाला जा सकता। पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया कि आदेश का अनुपालन स्वैच्छिक है, लेकिन इसे बलपूर्वक लागू किया जा रहा है। प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा इसकी निंदा की गई तथा इसे

विभाजनकारी कदम बताया। इस आदेश से समानता के अधिकार, अस्पृश्यता, भेदभाव का निषेध तथा कोई भी व्यापार करने के अधिकार का हनन कहा गया। वर्षों से चली आ रही यात्रा पर पहले कभी इस तरह के कोई आदेश नहीं जारी किए जाते रहे हैं। कांवड़ मार्ग में आने वाले ढाबे/रेहड़ी स्वयं प्रचार करते हैं कि उनके यहां शुद्ध वैष्णव भोजन मिलता है। दूसरे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट (एफएसएसआई) व स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जैसे कानून पहले ही मौजूद हैं। जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चत करने का काम करते हैं। बाजार में मिलने वाले भोज्य पदार्थ स्वच्छ हों, उनमें किसी तरह की मिलावट या गंदगी न हो, यह जांचना स्थानीय प्रशासन का काम है। सवाल सिर्फ कांवड़ श्रद्धालुओं का ही नहीं है बल्कि यह हर उपभोक्ता का अधिकार है कि उसे शुद्ध-स्वच्छ खाना मिले। बीते कुछ सालों से राज्य सरकारें कांवड़ यात्रा में विशेष रुचि ले रही हैं, जबकि इन्हीं राज्यों में और भी तीर्थ स्थल हैं, जो बुरी तरह उपेक्षित हैं या वहां किसी तरह की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता। हम सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही नहीं हैं बल्कि हमारी संस्कृति हमें सहिष्णुता व भाई-चारा भी सिखाती है। इस तरह के आदेशों से कारोबार बाधित होता है और नीचे के वर्ग को रोजगार या दिहाड़ी से हाथ धोना पड़ता है। साथ ही समाज में विभेद पैदा होगा। इस आदेश का सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व गरीब दुकानदारों को होता, जो रोज कमाने-खाने वाले हैं। राज्य सरकारों को अदालत के हस्तक्षेप से पूर्व ही विचारपूर्वक निर्णय लेने की आदत डालनी होगी।

भारी बारिश/डॉ. नन्दकिशोर साह

डूबने से बचा जा सकता है

बरसात में देश के विभिन्न क्षेत्रों में नदी, नहर, कुआं, तालाब, गहरे गड्ढे, झील, पोखर, जल प्रपात आदि जलाशयों में स्नान करने, जानवर नहलाने या कपड़े धोने जैसे रोजमर्रे के काम के दौरान अनजाने में बच्चों, किशोर-किशोरियों तथा वयस्क व्यक्तियों की डूबने से मौत होती रहती है। सावधानी, सतर्कता एवं जागरूकता के द्वारा इस अमूल्य जीवन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है।

खतरों की उपेक्षा या कमतर आंकना या गलत जानकारी, सही व सटीक जानकारियों के बिना नहर में जाना, निगरानी एवं पर्यवेक्षण की कमी, तैराकी का अभाव, कम उम्र के बच्चों को अभिभावकों द्वारा नदियों एवं तालाबों में नहाने के लिए अकेले छोड़ देना, पानी में डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए बिना तैयारी और अनुभव के पानी में कूद पड़ना आदि डूबने से होने वाली मौतों के प्रमुख कारण हैं। अगर आप भली प्रकार तैरना जानते हों तभी आप किसी को बचाने के लिए पानी में जाएं। यदि आप के निकट पानी में कोई डूब रहा है तो आप उसे बचाने के लिए पानी के बाहर से जो भी उपलब्ध साधन जैसे बांस का टुकड़ा, रस्सी, कोई लंबा कपड़ा जैसे साड़ी, धोती बाहर से फेंक कर डूबते हुए व्यक्ति को पकड़ने को कहें और उसे धीरे-धीरे बाहर खींच कर लाएं। किसी को डूबता देखकर मदद के लिए शोर मचाएं, जिससे आस-पास के सक्षम लोग मदद कर सकें। डूबे हुए या डूबते हुए व्यक्ति को पानी से बाहर निकालने पर देखें कि वह व्यक्ति होश में है या नहीं। होश में रहने पर उससे सामान्य तरह से बात कर ढांढस दें।

नदियों, नहरों, जलाशयों या अन्य जल निकायों के पास लिखी गई चेतावनी की अवहेलना न करें। छोटे बच्चों को घाटों, जल निकायों के समीप न जाने दें। एकदम से अनजान एवं सुनसान नदियों, नहरों, तालाबों के घाटों पर स्नान करने न जाएं। नदियों, नहरों या अन्य जल निकायों के घाट के किनारों पर पारंपरिक, धार्मिक, सामाजिक रीति-रिवाजों, अनुष्ठान, संस्कारों का निर्वहन करते समय किसी भी तरह की असावधानी न बरतें। तैरते या पानी में स्नान करते समय स्टंट न करें या सेल्फी आदि न लें, ऐसा करना जानलेवा हो सकता है।

सभी को साधने वाला

आम बजट

योगेश कु. गोयल

लोकसभा चुनाव से पहले इसी साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जुलाई में पूर्ण बजट में सरकार द्वारा विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा। अंतरिम बजट में न तो आम आदमी के लिए राहत की कोई विशेष घोषणाएं हुई थी और न ही उन पर कोई बड़ा बोझ लादा गया था, लेकिन अंतरिम बजट में भी सरकार का मुख्य फोकस गरीबों और महिलाओं पर ही दिखा था। आम बजट में हर वर्ग के लिए कुछ-न-कुछ राहत देने का प्रयास किया गया है। वैसे, सरकार का फोकस गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं पर दिखा है, साथ ही बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने का रोडमैप भी पेश किया गया है।

बजट में देश की समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ-साथ लोगों के निजी हितों का भी विशेष ध्यान रखा गया है, साथ ही उन सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को विस्तारित करने की भी घोषणा की गई है, जो मौजूदा समय में लोगों के निजी हितों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए इस वर्ष बजट आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपए है। बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो भारत की कुल जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा।

वित्तमंत्री के अनुसार 2024-25 तक वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है और सरकार का लक्ष्य घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे पहुंचना है। बजट में आम लोगों से लेकर तमाम करदाता टैक्स स्लैब में कमी, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और 80सी के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाए जाने की आस लगाए हुए थे। और वित्तमंत्री ने उन्हें निराश भी नहीं किया। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार नई आयकर दरों से करदाताओं को कम से कम 17500 रुपए की बचत होगी। वित्तमंत्री के मुताबिक नई कर व्यवस्था से सरकार को सात हजार करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा, लेकिन इससे चार करोड़ वेतनभोगियों को लाभ होगा। विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई है और आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा भी की गई है। हर तरह के स्टार्टअप्स के लिए एंजेल टैक्स हटाने का ऐलान किया गया है।

बजट में जिन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है, उनमें रोजगार और कौशल, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, शहरी विकास, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा सुरक्षा, अगली पीढ़ी के सुधार, विनिर्माण और सेवाएं, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, नवाचार, अनुसंधान और

विकास इत्यादि शामिल हैं। रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में युवाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और युवाओं को रोजगार के लिए तीन प्रमुख योजनाओं पर काम करने का ऐलान भी किया है। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपए प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी और प्रशिक्षण के दौरान होने वाले खर्च को कंपनी सीएसआर फंड से वहन करेगी।

वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना 32 प्रतिशत ज्यादा है। उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन को पहली बार कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना के माध्यम से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य 50 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है। छात्रों को 7.5 लाख रुपए 'मॉडल स्किल लोन' का लाभ देने का ऐलान भी बजट में किया गया है, जिससे उन छात्रों को लाभ पहुंचेगा, जो पैसों के अभाव में पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा भी बजट में है।

महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपए के आवंटन और मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 रुपए लाख रुपए की गई है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होंगे। विभिन्न क्षेत्रों के लिए की गई अन्य विशेष घोषणाओं में शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए, सड़क सम्पर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपए, बिहार में ग्रहवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपए, अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए, 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी इत्यादि शामिल हैं। आम आदमी को आम बजट में की गई घोषणाओं से जहां कुछ राहत मिली है तो कुछ चीजें महंगी होने से उनकी जेब पर बोझ भी बढ़ेगा। हां, कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाने से इलाज कुछ सस्ता होने की उम्मीदें बढ़ी हैं।

बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.48 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो शिक्षा मंत्रालय को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। 2023 में केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को 112898.97 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, वह भी उस समय तक का सबसे ज्यादा आवंटन था, लेकिन इस बार सरकार ने उस आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 89287 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 88956 करोड़ रुपए के आवंटन से थोड़ा ही ज्यादा है। इसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही थी। दरअसल, वैश्विक मानकों के अनुसार किसी भी देश को स्वास्थ्य पर कम से कम 3 फीसद खर्च करना चाहिए, जबकि भारत में स्वास्थ्य पर करीब 1.3 फीसद ही खर्च हो पा रहा है। बहरहाल, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त आम आदमी के लिए सरकार ने बजट में कुछ बड़ी राहतों का जो पिटारा खोला है, उसे देखते हुए इस बजट को सभी वर्गों को साधता संतुलित बजट कहा जा सकता है।

दरअसल, वैश्विक मानकों के अनुसार किसी भी देश को स्वास्थ्य पर कम से कम 3 फीसद खर्च करना चाहिए, जबकि भारत में स्वास्थ्य पर करीब 1.3 फीसद ही खर्च हो पा रहा है। बहरहाल, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त आम आदमी के लिए सरकार ने बजट में कुछ बड़ी राहतों का जो पिटारा खोला है, उसे देखते हुए इस बजट को सभी वर्गों को साधता संतुलित बजट कहा जा सकता है

- जॉब फिक्शन के मोर्चे पर दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉब की जरूरत के मुताबिक स्किल नहीं होने की समस्या बड़ी है', यह कहना है कि इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन (आईएसएफ) का
- आईएसएफ के कार्यकारी निदेशक सुविता दत्ता के मुताबिक, एक चुनौती यह भी है कि दक्षिण में जॉब के मौके अधिक हैं, लेकिन स्किल्ड लोग पूर्व और पश्चिम भारत में अधिक हैं
- यही कारण है कि स्टाफिंग इंडस्ट्री को माइग्रेंट वर्कर्स को स्किल सिखाकर काम करने लायक बनाने पर खासा खर्च करना पड़ता है

(चित्र : नीरज हलूदुरू)

जब अरुण जेटली विपक्षी नेता थे तो अपने भाषण में विस्तार से बताया था कि क्यों 5 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त होना चाहिए। भाजपा के सत्ता में आने के 11 साल बाद भी जेटली जी की वह गणित जमीन पर उतरने वाली है। कर मुक्त आय की सीमा पिछली बार के 3 से एक इंच आगे नहीं खिसक सकी।

रंगनाथ सिंह, पत्रकार
@rangnathsingh_

पटेल की सीख और पूजा खेडकर

मुद्दा डॉ. आर.के. सिन्हा

लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने 21 अप्रैल, 1947 को राजधानी के मेटकॉफ हाउस में आजाद होने जा रहे भारत के पहले बैच के आईसीएस जो 1948 से आईपीएस कहलाए; ऐसे सभी अफसरों को संबोधित करते हुए कहा था कि 'उन्हें स्वतंत्र भारत में जनता के सवालों को लेकर गंभीरता और सहानुभूति का भाव रखना होगा। उन्हें अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी से करना होगा।' सरदार पटेल ने उन्हें स्वराज और सुराज का अंतर भी समझाया था। जाहिर है, उनका ईमानदारी से आशय यही रहा होगा कि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में शुचिता और तटस्थता का पालन करेंगे। पर हाल में आईएएस प्रोबेशनर, पूजा खेडकर मामले को गहराई से देखने से समझ आ रहा है कि कुछ शातिर तत्व आईएएस या अन्य सरकारी नौकरियों को पाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र भी सौंपते हैं। उनके लिए ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है। उन्हें सरदार पटेल की सीख से भी कोई लेना-देना नहीं।

पूजा खेडकर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण ले रही थीं। उन्हें महाराष्ट्र-उनके अपने राज्य कैडर-में जिला प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। उन्हें एहसास नहीं था कि आईएएस अफसर बनने का मतलब जन सेवा होता है। इसके बजाय, उसने इस पद को हासिल करने के बाद अपनी झूठी शान दिखानी शुरू कर दी। उसने कार, सुसज्जित कार्यालय और कर्मचारियों जैसी कई सुविधाओं की मांग की। चूंकि प्रोबेशनर्स इन लाभ के हकदार नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी लाभ नहीं दिया गया। इसलिए, उसने अपनी दैनिक जरूरतों के लिए एक लग्जरी कार 'किराए पर' ली। इससे भी बुरा यह है कि उन्होंने कार की छत पर नीली बीकन लाइट भी लगाई। पूजा का चयन दो विशेष श्रेणियों के तहत किया गया था। एक, वह ओबीसी के गैर-क्रीमी वर्ग से संबंधित हैं। यह स्वयं ही संदिग्ध है, यह देखते हुए कि उनके पिता एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे। फिर वह गैर-क्रीमी लेयर में कैसे चुनी गईं? उनके परिवार के पास पर्याप्त जमीन है जो निश्चित रूप से उन्हें एक अलग आर्थिक श्रेणी में रखेगी। पूजा ने यह भी दावा किया था कि उसकी एक अलग तरह की शारीरिक स्थिति है, जो उसे विकलांग कोटे के तहत आरक्षित सीट के लिए हकदार बनाती है। यूपीएससी और कार्मिक विभाग द्वारा विकलांगता के संबंध में कुछ तय दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं। एक व्यक्ति जिसे एक आंख में दृष्टि नहीं होती है,

उसे 'विकलांग' नहीं माना जाता है, यदि दूसरी आंख हर तरह से ठीक है। मैंने इसके बारे में तब जाना जब मेरे एक मित्र के पुत्र ने सिविल सेवा परीक्षा दी।। बचपन में, उसके एक भाई ने उसकी दाहिनी आंख में केंपास (नुकीली चीज) डाल दी थी, जिससे वह आंशिक रूप से अंधा हो गया था। वह विकलांग कोटे के तहत आरक्षण के लिए योग्य नहीं होता, अगर उसकी दूसरी आंख सही होती। उसकी 'सामान्य' आंख में आंशिक अंधापन था। कुल मिलाकर अगर पूजा ने नखरे नहीं दिखाए होते, तो वह सेवा में बनी रहती। इससे कांड के बाद यूपीएससी की कार्यप्रणाली भी अच्छी रोशनी में नहीं दिखता है। इस बीच, तेलंगाना में एक आईएएस अधिकारी के बारे में भी रिपोर्ट आई है, जो कुछ विकलांगताओं के आधार पर सेवा में शामिल हुए। उदाहरण के लिए, उन्हें कथित तौर पर पोलियो का हमला हुआ है, लेकिन घोड़े की सवारी और साइकिल चलाते हुए उनके वीडियो यह तो नहीं बताते कि वे कभी पोलियो के शिकार थे। इससे यह सवाल उठता है कि क्या सिविल सेवाओं में विकलांग श्रेणियों के तहत रिक्तियों को भरने में मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाता है। लगता तो यही है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और पिछले दस-पंद्रह साल में विकलांगता के आधार पर चुने गए ऐसे सभी मामलों को जांच के दायरे में लाने की आवश्यकता है। आईएएस, जिसे अक्सर 'भारत के इस्पात फ्रेम' के रूप में जाना जाता है, यह उपाधि सरदार वल्लभभाई पटेल, 'भारत के लौह पुरुष' से प्राप्त करता है। उन्होंने नव स्वतंत्र भारत की एकता और स्थिरता बनाए रखने में सिविल सेवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। आईएएस राष्ट्र के प्रभावी शासन के लिए आवश्यक, सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। यदि देश की जनता के दिल में आईएएस पदाधिकारियों के प्रति स्वाभाविक रूप से सम्मान और आदर का भाव नहीं रह जाएगा, तो कोई भी आईएएस प्रशासन कर ही नहीं पाएगा।

आईएएस अधिकारियों से अपनी भूमिकाओं में निष्पक्षता और अखंडता का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। उनके फैसले लाखों लोगों के जीवन और देश की समग्र स्थिरता को प्रभावित करते हैं। निष्पक्षता बनाए रखकर और कानून के शासन का पालन करके, आईएएस अधिकारी यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सरकार की नीतियां और कार्यक्रम निष्पक्ष रूप से और प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया से समझौता पक्षपात ला सकता है और कानून के शासन को कमजोर कर सकता है, जिससे अस्थिरता और जनता का विश्वास कम हो सकता है। पूजा खेडकर का मामला इस बात की गवाही है कि हमारे देश में फर्जी प्रमाणपत्र दिखाकर मलाई खाने का खेल खूब चल रहा है, जिसे बंद किए जाने की आवश्यकता है।

आनंदमय पुरुष बनना सद्गुरु

हर व्यक्ति के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है एक आनंदमय मनुष्य बनना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में किसके पीछे जा रहे हैं, चाहे व्यापार, पैसा, परिवार या आध्यात्मिकता, यह बस खुशी पाने का प्रयास है। आपने हमशा समझा है कि खुश होने का मतलब है कि आप वह कर पा रहे हैं, जो

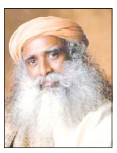

आप करना चाहते हैं, और जो आप बाहरी दुनिया में हासिल करना चाहते हैं। खुश और शांतिमय होना एक सफल जीवन का चरम पहलू माना जाता है, लेकिन ये जीवन का वाकई सबसे बुनियादी पहलू है। कई तरीकों से, लोगों की खुशी बाहरी स्थितियों पर निर्भर करती है। जब आप बाहरी स्थितियों पर निर्भर हों, तो आप अपने जीवन में कभी स्थाई आनंद नहीं जानेंगे, क्योंकि बाहरी चीजों पर आपका कभी पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा। जब आप अपने कार्यों द्वारा खुशी खोजते हैं, तो आप हमेशा बाहरी चीजों के गुलाम होते हैं। जब आप गुलाम होते हैं, तो आप हमेशा पीड़ा के किसी स्तर में रहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति के पास क्या है, उसमें फिर भी कुछ और पाने की लालसा हर समय होगी। जब तक कि व्यक्ति को खुशी का आंतरिक आधार नहीं मिल जाता, वह हमेशा एक भिखारी की तरह जिएगा। आप अपने जीवन में जिसे भी खुशी, या प्रेम, या शांति समझते या अनुभव करते हैं, उसका एक खास आंतरिक आधार होता है। आज अगर आप मानसिक शांति खो देते हैं, तो आपका डॉक्टर आपको एक गोली दे देगा। यह रसायन आपके शरीर के अंदर जाकर आपको शांत बना देता है, बस थोड़ी देर के लिए। या दूसरे शब्दों में, जिसे आप शांति कहते हैं, वह आपके भीतर एक खास तरह की रासायनिकता है। इसी तरह से, जिसे आप आनंद, या प्रेम, या पीड़ा, या डर कहते हैं, प्रत्येक अनुभव का आपके भीतर एक रासायनिक आधार होता है। योग की पूरी प्रक्रिया आपकी आंतरिकता को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में लाने के लिए है। यह बाहरी दासता की अवस्था से आंतरिक पूर्णता की ओर, जो असीमता की अवस्था है, जाने की संभावना है। अगर आपकी आंतरिक प्रकृति असीम है, तो आपका जीवन भी असीम है।

रीडर्स मेल

'सुप्रीम' फैसला

मैं सोचता हूं अगर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट न होता तो क्या होता? सरकारों का मनमानी एवं तानाशाही के कारण नागरिकों को आत्महत्या करने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प उसके पास नहीं होता। अब देखिए न सावन के शुरू होते ही इन लोगों ने मिलकर एक साजिश के तहत बाजारों में, कांवड़ निकलने के सारे रास्तों में पड़ने वाले दुकान, ढाबा आदि दुकानदारों तथा वहां काम करने वालों का नाम लिख कर प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया था। सबसे पहले था उत्तर प्रदेश, फिर आया उत्तराखंड फिर उसमें शामिल हो गया मध्य प्रदेश। ये तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों की मंशा को समय रहते पकड़ लिया और सावन के पहले ही दिन यानी सोमवार 22 जुलाई को अंतरिम आदेश देकर, मेन प्लेट लगाने के निर्णय पर रोक लगा दिया। मेन प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और इस पर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। यह एक तरह से अल्पसंख्यक दुकानदारों को पहचानकर उनके आर्थिक बहिष्कार जैसा है।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर, झारखंड

महिलाओं की बल्ले-बल्ले

वित्त मंत्री ने बजट में खासकर महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। महिलाओं और बालिकाओं को बजट में फायदा पहुंचाते हुए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। वहीं इस बार केंद्र सरकार ने अपने बजट में महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए खासकर कामकाजी महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाने का ऐलान किया है। सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और महिलाओं को पीएफ में एक महीने का वेतन दिया जाएगा। देश के 4.1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे देश के युवाओं को बड़ा फायदा होने वाला है। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया है। पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए की गई है। बजट में इन दोनों बदलावों से नौकरीपेशा और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलेगा।

दीपिका मित्तल, ई मेल से

परिधान का सम्मान जरूरी

विगत दिनों एक अच्छा समाचार पढ़ने को मिला कि बेंगलूरु में एक व्यक्ति को धोती पहनने पर प्रवेश करने से रोकने वाले शॉपिंग मॉल को सरकार ने सात दिन के लिए बंद करवा दिया। यह देखना सुखद है कि धोती पहनने वाले व्यक्ति के अधिकार का हनन करने वाले शॉपिंग मॉल के खैवैये को विधानसभा अध्यक्ष ने वहां उठाया और सरकार ने कार्रवाई भी कर दी। आखिर भारत में ही भारतीय पहनावा पहनने वालों का अपमान क्यों होना चाहिए? धोती-कुर्ता तो हमारे देश का गौरवशाली परिधान है। यह हमारे भारतीय होने का एक परिचय है। अब सरकार को नियम बना देना चाहिए कि धोती पहनने वाले को यदि किसी भी सार्वजनिक जगह पर प्रवेश से रोका जाता है, तो उस संस्थान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

गोपाल सोनी, मनावर, धार (मप्र)
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीय • सशक्त • सशक्त

सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नरसंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
| समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र® ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370. दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-33, अंक 341
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के भाषण एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी